

भारतीय एआरसी: उनके व्यवसाय परिचालन और एनपीए समाधान में उनकी भूमिका का अध्ययन*

भारत ने बैंकिंग संकटों के बाद कई अन्य देशों के विपरीत अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के एक भाग के रूप में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को निजी क्षेत्र की संस्थाओं के रूप में शुरू किया, जबकि अन्य देशों ने ऐसी संस्थाओं को बतौर सार्वजनिक क्षेत्र मॉडल शुरू किया। भारतीय एआरसी के विकास में वृद्धि और सुस्ती के चरण देखने को मिलते हैं जिसे उभरती समष्टि-वित्तीय स्थितियों और विनियामक परिवर्तनों ने आकार दिया है। एआरसी क्षेत्र खासकर बैंकों से प्राप्त घरेलू पूंजी पर निर्भर होते हैं। बही मूल्य की तुलना में अधिग्रहण की लागत का अनुपात कम बना हुआ है, भले ही वह धीमी वृद्धि कर रहा है और भिन्न-भिन्न एआरसी तथा क्षेत्रों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। एआरसी की बहियों में ऐसी प्रतिभूति रसीदों की काफी भरमार है जो बहुत पुरानी है।

1. परिचय

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए पिछले दशक से आस्ति गुणवत्ता में गिरावट लगातार चिंता का विषय रही है। वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद की अवधि में बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात, जो काफी हद तक अपरिवर्तित रहा था, 2011 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ और 2015 के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई (आरबीआई, 2018)। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सक्रिय आस्ति गुणवत्ता निर्धारण को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शुरू की।

हालांकि बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य के सही आकलन के लिए सक्रिय आस्ति निर्धारण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए बैंकों द्वारा प्रभावी आस्ति समाधान और वसूली का पालन करने की आवश्यकता है। एक प्रभावी समाधान और वसूली तंत्र का अभाव (अक्सर आस्ति पुनर्निर्माण के रूप में संदर्भित) सबसे पहले बैंकों द्वारा एनपीए निर्धारण को हतोत्साहित कर सकता है।

* यह लेख पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) के अमरनाथ यादव और पल्लवी चव्हाण द्वारा तैयार किया गया है। डीओएस के पूर्व सीजीएम आर रविकुमार से प्राप्त मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं तथा संगठन के नहीं हैं जिससे वे संबंधित हैं।

समय पर वसूली का सहारा न मिलने से आस्तियों का आर्थिक मूल्य भी कम हो सकता है जिससे कालांतर में बैंकों को होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है।

इस लेख में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर निगाह डाली गई है, जिसकी भारत में आस्ति समाधान तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2002 में शुरू होने के बावजूद, एआरसी का विकास न तो सुचारू रहा है और न ही स्थिर रहा है। इन संस्थाओं में आंशिक रूप से समष्टि-वित्तीय स्थितियों और आंशिक रूप से विनियामक वातावरण में परिवर्तन के कारण वृद्धि और सुस्ती के चरण देखने को मिलते हैं। इस लेख में इन संस्थाओं के विकास का पता लगाया गया है, और उनकी संरचना और व्यवसाय परिचालन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है, और इस तरह एनपीए समाधान में उनकी भूमिका का विश्लेषण भी किया गया है। इन संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रासंगिक नीतिगत परिवर्तनों पर भी चर्चा की गई है। इस लेख में भारतीय एआरसी मॉडल की अन्य देशों के मॉडल के साथ तुलना की गयी है और उससे उभरने वाली अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है।

शेष लेख छह खंडों में विभाजित है। खंड 2 में एआरसी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ भारत में एनपीए समाधान तंत्र की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की गई है। खंड 3 में भारतीय एआरसी मॉडल की तुलना अन्य देशों के मॉडल से की गयी है। खंड 4 में भारतीय एआरसी उद्योग की प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि खंड 5 इन कंपनियों के व्यवसाय परिचालन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करता है। खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है, और एआरसी के भविष्य के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

2. एआरसी के विशेष संदर्भ में आस्ति समाधान तंत्र का विकास

एक प्रभावी आस्ति समाधान तंत्र उत्कृष्ट कार्यशील वित्तीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसी मान्यता के साथ वित्तीय प्रणाली समिति (सीएफएस) की सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय क्षेत्र सुधारों के भाग के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए शोध्य ऋण वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम 1993 पारित किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से नरसिंहम समिति I के नाम से

जाना जाता है। आरडीडीबीएफआई अधिनियम लागू होने पर ₹10 लाख (2018 में इसे ₹20 लाख तक बढ़ा दिया गया) की आर्थिक सीमा से जुड़े मामलों की कर्ज वसूली से निपटने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) को विशेष न्यायाधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। डीआरटी को ₹20 लाख तक की राशि से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए लोक अदालत बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया था।¹

डीआरटी ने एक आशाजनक शुरुआत की थी, प्रारंभिक वर्षों में इन न्यायाधिकरणों के माध्यम से वसूल की गई राशि प्रतिशत के रूप में दोहरे अंकों में थी और 2008-09 में बढ़कर 81 प्रतिशत तक पहुंच गई थी (सारणी 1)। हालांकि, बाद के वर्षों में वसूली की दर घटकर एकल अंकों में आ गई; 2019-20 में, डीआरटी के माध्यम से वसूल की गई राशि का प्रतिशत वसूली योग्य राशि का लगभग 4 प्रतिशत था। इन विशेष न्यायाधिकरणों का निर्माण त्वरित समाधान के लिए किया गया था ताकि दीवानी अदालतों

पर कर्ज से संबंधित मामलों का बोझ हल्का किया जा सके। हालांकि, वास्तव में, इन न्यायाधिकरणों द्वारा, आंशिक रूप से उनके अत्यधिक बोझ और अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण (भगवती और अन्य, 2017) निपटान में काफी देरी हुई।

वर्ष 2002 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) के पारित होने से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूति हित लागू करके और बिना किसी अदालती हस्तक्षेप के उधारकर्ताओं की आस्ति की नीलामी से जमानती कर्ज की वसूली करने का अधिकार मिला। भारत में एनपीए समाधान के लिए सरफेसी अधिनियम के भाग के रूप में एक अन्य संस्थागत विकल्प के रूप में, एआरसी को स्थापित किया गया था। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित एआरसी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए बनाई गई संस्थाएं थीं।

सारणी 1: बैंकों, विभिन्न चैनलों द्वारा वसूल किए गए एनपीए का संवितरण

वर्ष	लोक अदालत			डीआरटी			एआरसी			आईबीसी			कुल	
	अंतर्निहित राशि का प्रतिशत	वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि का प्रतिशत	वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि का प्रतिशत	वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि का प्रतिशत	वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि का प्रतिशत	अंतर्निहित कुल राशि (₹ करोड़)	वसूल की गई कुल राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2003-04	5.1	3.3	13.5	53.3	79.1	30.9	41.5	17.6	8.9	-	-	-	47535	9921
2004-05	2.8	2.2	14.1	50.5	51.8	18.8	46.7	46.1	18.1	-	-	-	28342	5192
2005-06	6.5	2.7	20.3	35.9	56.4	76.9	57.6	41.0	34.8	-	-	-	17055	8356
2006-07	4.0	1.4	14.0	48.3	47.3	37.8	47.7	51.2	41.4	-	-	-	18972	7318
2007-08	14.1	2.3	8.2	38.2	39.6	51.9	47.7	58.1	61.0	-	-	-	15224	7625
2008-09	19.9	1.3	2.4	20.4	45.1	81.1	59.7	53.6	33.0	-	-	-	20220	7426
2009-10	23.1	1.5	1.5	31.3	41.7	32.0	45.6	56.8	30.0	-	-	-	31281	7514
2010-11	10.5	1.0	2.9	28.2	25.1	27.9	61.3	73.9	37.8	-	-	-	49950	15642
2011-12	2.8	1.4	11.8	39.4	28.5	17.0	57.8	70.1	28.6	-	-	-	61100	14400
2012-13	6.2	1.7	6.1	29.3	18.9	14.2	64.4	79.4	27.2	-	-	-	105700	23300
2013-14	13.3	4.4	6.0	31.8	16.6	9.6	54.8	79.1	26.5	-	-	-	173800	32000
2014-15	12.5	3.2	3.2	24.3	13.6	7.0	63.2	83.1	16.3	-	-	-	248200	30800
2015-16	32.5	14.0	4.4	31.3	28.1	9.2	36.2	57.9	16.5	-	-	-	221400	22800
2016-17	13.0	6.0	6.4	36.2	26.8	10.2	50.8	67.3	18.3	-	-	-	278300	38500
2017-18	16.9	4.5	4.0	49.2	17.9	5.4	30.3	65.4	32.2	3.7	12.2	49.6	270631	40352
2018-19	7.4	2.3	5.1	37.0	8.9	3.9	35.6	32.8	15.0	20.4	56.2	45.7	725996	118647
2019-20	9.1	2.4	6.2	33.1	5.8	4.1	26.5	30.5	26.7	31.3	61.3	45.5	742431	172565

* वसूल की गई राशि दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि है, जो दिए गए वर्ष के साथ-साथ पहले के वर्षों के मामलों के संदर्भ में भी हो सकती है।

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट।

¹ बैंकों और अनर्जक उधारकर्ताओं के बीच एक नागरिक निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के भाग के रूप में लोक अदालत विकसित की गई थी। छोटे ऋणों के संबंध में बकाया राशि के निपटान के लिए लोक अदालत उपयोगी रही है। वर्ष 2019-20 में, लोक अदालत के समक्ष ₹67,801 करोड़ रुपये राशि के लिए 59,86,790 मामले लंबित थे, जो इन संस्थाओं के छोटे आकार के अभिविन्यास को दर्शाते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (नरसिंहम समिति II) की सिफारिशों के बाद एआरसी का निर्माण एक महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र का सुधार था, जिससे जमानती आस्तियों के समाधान और वसूली की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद थी। अंततः 2016 में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) आयी जिसने एनपीए समाधान तंत्र को कई कदम आगे बढ़ाया, इस कोड से कॉर्पोरेट और व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा जमानती और गैर-जमानती ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा की गई थी।²

आईबीसी एनपीए समाधान से संबंधित अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार रहा है। वर्ष 2019-20 में, आईबीसी के तहत अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि 45.5 प्रतिशत थी और एआरसी के लिए 26.7 प्रतिशत थी। जबकि एआरसी की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एआरसी के माध्यम से वसूल की गई राशि अंतर्निहित राशि के प्रतिशत के रूप में काफी अधिक थी, हाल के वर्षों में, 2017-18 के उछाल को छोड़कर यह 30 प्रतिशत से नीचे गिर गयी है।

हालांकि, एआरसी बैंकों के लिए कर्ज वसूली का एक महत्वपूर्ण चैनल बना हुआ है और आईबीसी के बावजूद आस्तित्व प्रबंधन के क्षेत्र में एआरसी को भूमिका निभानी है।³ आईबीसी की शुरुआत से वसूली के सभी चार चैनलों में शामिल कुल राशि में उनकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रही है। इसके अलावा, सभी चैनलों के माध्यम से वसूल की गई कुल राशि में उनका लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है।

3. भारतीय एआरसी मॉडल की अन्य देशों के मॉडल के साथ तुलना

एआरसी शब्द भारतीय संदर्भ में प्रयोग में रहा है; इसका आम वैश्विक समानांतर आस्तित्व प्रबंधन कंपनी (एएमसी) है। एएमसी के

दो रूप हैं, एक जो बैंक समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दूसरे जो एनपीए समाधान (सेरुती, 2018) से संबंधित हैं।

अन्य देशों में एनपीए समाधान से निपटने वाले एएमसी के कई प्रयोग हुए हैं। स्वीडन का सिक्वोरम जो 1992 में स्थापित किया गया था और 1997 में बंद किया गया, कुछ सफल एएमसी में शामिल हैं, और अंतर्निहित राशि के लगभग 86 प्रतिशत राशि वसूल करने में सफल रहा है (बर्गस्ट्रॉम और अन्य 2003)। इसी तरह, मलेशिया का दनाहर्ता, जो एशियाई वित्तीय संकट के बाद स्थापित किया गया तथा 1998 और 2005 के बीच कार्यरत रहा, शामिल राशि का लगभग 58 प्रतिशत वसूल करने में कामयाब रहा (ड्रेयर, 2020)। विश्व बैंक द्वारा समीक्षा किए गए एएमसी प्रयोगों में, 1989 से 1997 तक अस्तित्व में रहे घाना के अनर्जक आस्तित्व न्यास (एनपार्ट) का प्रदर्शन, संतोषजनक माना गया (विश्व बैंक 1997)।

उपरोक्त में से प्रत्येक एएमसी सरकार के स्वामित्व वाली थी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जुड़े प्रयोग भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, स्पेन ने 15 वर्षों की अवधि के लिए 2012 में सारेब बनाया, जिसमें निजी और सार्वजनिक इक्विटी (स्पेनिश बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित) 55:45 के अनुपात में (सेरुती, 2018 और ईवाई, 2020) शामिल हैं। इसी तरह, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 में आयरलैंड ने राष्ट्रीय आस्तित्व प्रबंधन एजेंसी (एनएएमए) की स्थापना की, जिसकी इक्विटी में निजी निवेशकों और राज्य खजाने का क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हिस्सा है (उक्त)।

कुछ देशों में एएमसी को भी सरकार समर्थित बॉन्ड से वित्तपोषित किया गया था। उदाहरण के लिए, एशियाई वित्तीय संकट के बाद स्थापित दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के एएमसी बजट संसाधनों (फंग और अन्य, 2004) पर तनाव को कम करने के लिए मुख्य रूप से सरकार समर्थित एएमसी बॉन्ड पर निर्भरता रही। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं, जो भारत के समान पूरी तरह से निजी क्षेत्र के एएमसी हैं। उदाहरण के लिए, बैंकअक्विएनगेजेलशाफ्ट (बीएजी) जर्मन सहकारी बैंकों का एक फेडरल संघ है जो इन बैंकों के समस्याग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन में विशेषज्ञता रखता है।

² आईबीसी पर विवरण के लिए, आईबीबीआई (2019) देखें।

³ दरअसल, एसेट रिजॉल्यूशन के लिए पहले के संस्थागत विकल्पों के स्थान पर आईबीसी को पूरक के रूप में देखना जरूरी है। इसका कारण यह है कि आईबीसी न सिर्फ इन विकल्पों पर बनता है बल्कि उनका समर्थन भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, डीआरटी को आईबीसी के तहत व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के दिवालियेपन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों के रूप में नामित किया गया है। इसी तरह, एक कुशल दिवालियापन शासन की उपलब्धता आस्तित्व प्रबंधन कंपनियों की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है; खंड 3 में चर्चा की गई अन्य देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को देखें।

एएमसी प्रयोगों पर पहले की गयी चर्चा से उभरने वाली सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: ए. अधिकांश देशों में एएमसी को घरेलू और/या वैश्विक बैंकिंग संकट या संकट जैसी स्थिति के बाद स्थापित किया गया था जिसके कारण बैंकों के अनर्जक ऋणों में वृद्धि हुई थी; बी. अधिकांश एएमसी एक पूर्व-निर्धारित अवधि के लिए अस्तित्व में थे; सी. अधिकांश एएमसी को या तो प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी या सरकार के समर्थन से स्थापित किया गया था।

निसंदेह, भारतीय एआरसी मॉडल कुछ मौलिक तरीकों से अन्य देशों के मॉडलों से अलग है। सबसे पहले, भारत में एआरसी की स्थापना ऐसे समय में की गई थी जब बैंकों का एनपीए अनुपात काफी अधिक था; सकल एनपीए अनुपात 1998 और 2002 के बीच बढ़ रहा था और 10-14 प्रतिशत के दायरे में था। जबकि एनपीए में बढ़ती प्रवृत्ति को आस्ति समाधान तंत्र मजबूत करने के लिए एक आसन्न कारण के रूप में समझा जा सकता है, एआरसी स्थापित करने का कदम अंततः वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की व्यापक प्रक्रिया से जुड़ा था और इसे प्रतिक्रियाशील की तुलना में अधिक सक्रिय होने के रूप में माना जा सकता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नरसिंहम समिति II की सिफारिशों के फलस्वरूप सरफेसी अधिनियम पारित हुआ था।⁴

दूसरी बात यह है कि चूंकि उन्हें किसी विशिष्ट संकट का समाधान करने का कार्य नहीं दिया गया था, इसलिए भारतीय एआरसी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए स्थापित नहीं किए गए थे। तीसरा, भारतीय एआरसी रिजर्व बैंक में पंजीकृत निजी क्षेत्र की संस्थाएं रही हैं। अन्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के एएमसी ने अक्सर सरकारी वित्तपोषण या सरकार समर्थित वित्तपोषण (सेरुती और नेएन्स, 2016) का सहारा लिया है। इसके विपरीत, भारतीय एआरसी के लिए पूंजी की कमी, अक्सर चिंता के विषय के रूप में उल्लेख किया जाता है (भगवती और अन्य, 2017)।

हाल ही में, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एनपीए समस्या के समाधान के लिए सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित आस्ति पुनर्निर्माण और आस्ति प्रबंधन कंपनी की

⁴ श्री टी आर अंध्यारुजिना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रतिभूतिकरण के बारे में कानूनी पहलुओं का आगे अध्ययन किया गया। इसलिए, सरफेसी अधिनियम को अक्सर नरसिंहम द्वितीय और अंध्यारुजिना समितियों दोनों का परिणाम माना जाता है।

घोषणा की है।⁵ ऐसी कंपनी की स्थापना में, एएमसी पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं एक उपयोगी मार्गदर्शक हो सकती हैं। विश्व बैंक और वित्तीय स्थिरता संस्थान के अनुसार, एएमसी प्रयोग, जिनमें पहले चर्चा की गई थी, अपने मूल अधिदेश को पूरा करने में सफल रहे, वे थे: (i) स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के साथ एक संकीर्ण अधिदेश (जैसे एनपीए का निपटान); (ii) एक सावधि विधि खंड जो उनके कार्य काल को परिभाषित करता है; (iii) दिवालियेपन और निजी आस्ति कानूनों को शामिल करने वाली सहायक कानूनी अवसंरचना; (iv) समस्या ऋणों को पहचानने के लिए एक मजबूत राजनीतिक समर्थन; (v) प्रशासन, पारदर्शिता और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (सेरुती और नेयन्स, 2016; फंग और अन्य, 2004) सहित एएमसी का एक व्यावसायिक फोकस।

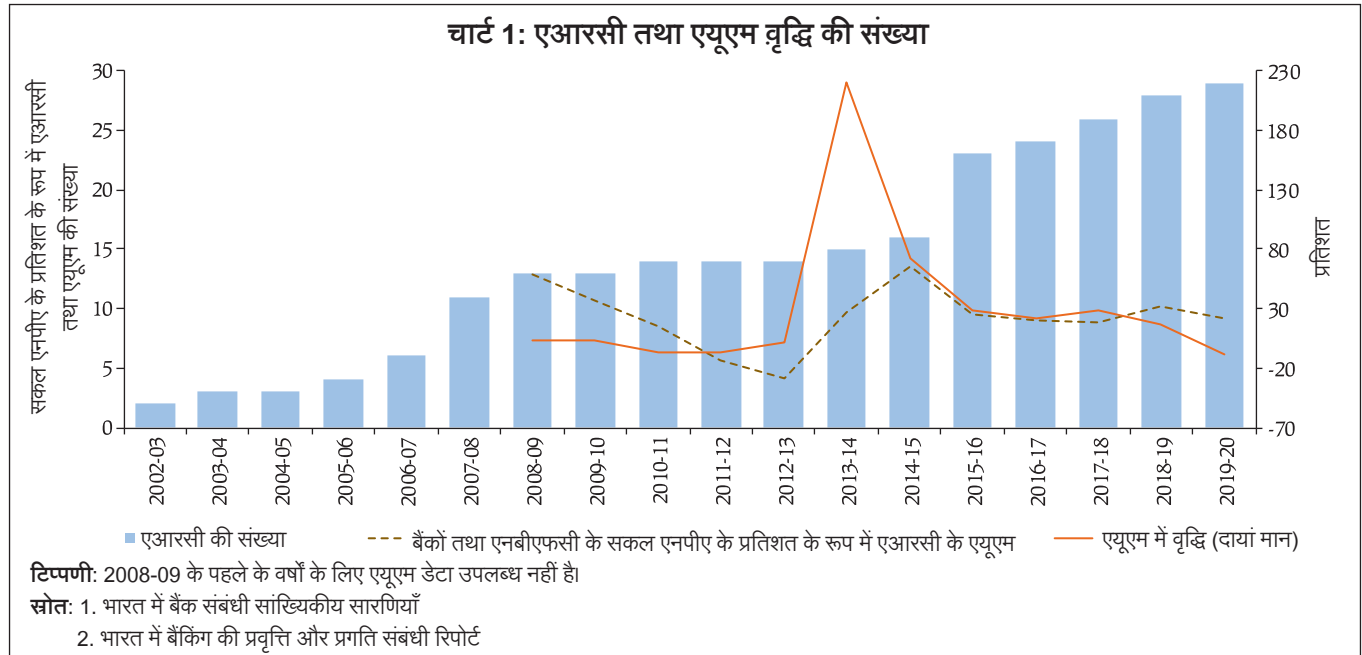
4. भारतीय एआरसी उद्योग की प्रमुख विशेषताएं

4.1 उद्योग का विकास

एआरसी उद्योग का विकास समय के अनुरूप नहीं रहा है और बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एनपीए के रुझानों के साथ हमेशा समकालिक नहीं रहा है। एआरसी उद्योग की शुरुआत 2003 में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआरसीआईएल) की स्थापना से हुई थी। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में मंद रहने के बाद, 2008 में और फिर 2016 में एआरसी की संख्या में एक उछाल देखा गया (चार्ट 1)। वर्ष 2013-14 में एक बड़े उछाल को छोड़कर एआरसी की संख्या में वृद्धि के बावजूद, प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) में वृद्धि काफी हद तक प्रवृत्तिहीन रही है।⁶ बैंकों और एनबीएफसी के एनपीए की मात्रा की तुलना में, 2013-14 के आसपास एयूएम में उच्च वृद्धि की अवधि को छोड़कर एआरसी के एयूएम में गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

⁵ देखें https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf पर यूनिथन बजट भाषण - 2020-21 और "New ARC aimed at specific set of bad assets with PSBs: Das", 26 फरवरी 2021 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और "Govt may provide some guarantee for bad bank, says FM", 8 फरवरी, 2021 का इकोनॉमिक टाइम्स।

⁶ इस उछाल को 2011 के बाद की आर्थिक मंदी के भाग के रूप में समझाया जा सकता है, जिसमें बैंकों के एनपीए में वृद्धि देखी गई, खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। भगवती और अन्य (2017) का तर्क है कि 2014 में एआरसी से संबंधित दिशा-निर्देशों में बदलाव के कारण भी यह उछाल आया है।



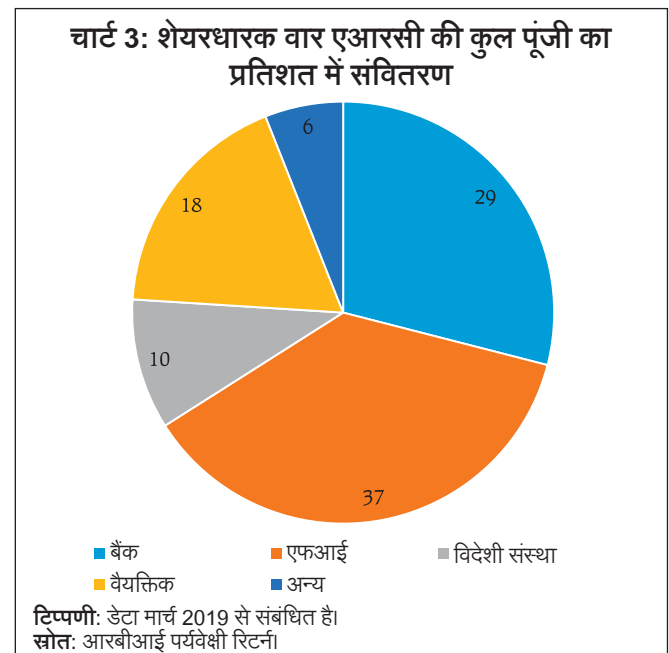
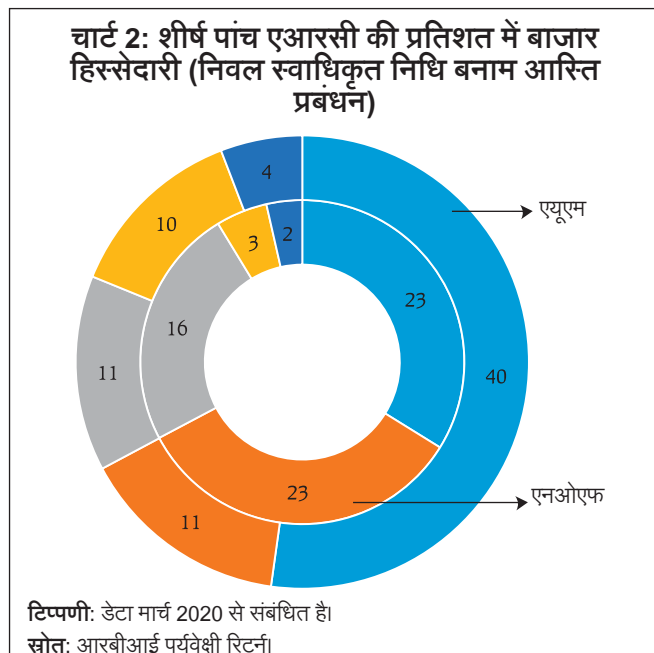
4.2 संकेन्द्रण

हालांकि समय के साथ एआरसी की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनका व्यवसाय अत्यधिक केंद्रित रहा है। मार्च 2020 में कुल एयूएम में से, लगभग 62 प्रतिशत और 76 प्रतिशत क्रमशः शीर्ष-तीन और शीर्ष-पांच एआरसी के पास थे। इसके अलावा, उद्योग के पूंजी आधार के संदर्भ में, 62 प्रतिशत शीर्ष तीन एआरसी

के पास था; शीर्ष पांच एआरसी के लिए संबंधित हिस्सेदारी 67 प्रतिशत थी (चार्ट 2)।

4.3 शेयरधारिता पैटर्न

निजी क्षेत्र की संस्थाएं होने के नाते, एआरसी के प्रमुख शेयरधारक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं (चार्ट 3)। अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए, एआरसी को 2016 में स्वचालित



मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।⁷ एफडीआई से संबंधित उदारीकरण के बावजूद, इन कंपनियों की कुल पूंजी में विदेशी संस्थाओं का हिस्सा छोटा ही है।

5. एआरसी के व्यवसाय परिचालन की मुख्य विशेषताएं

एआरसी के व्यवसाय मॉडल में तीन चरण हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

चरण 1: एआरसी द्विपक्षीय सौदों या नीलामी के माध्यम से बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से एनपीए प्राप्त करते हैं। आस्ति अधिग्रहण के बाद, वे इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से स्थापित एक या एक से अधिक न्यासों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) से प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की सदस्यता के लिए योजनाएं बनाते हैं।⁸ अर्जित एनपीए आस्तियां-विशिष्ट या पोर्टफोलियो-विशिष्ट योजनाओं में रखी जाती हैं; पूर्व योजना को तब अपनाया जाता है जब किसी बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त कुल कर्ज बड़ा होता है, जबकि बाद की योजना तब लागू की जाती है जब अधिगृहीत कर्ज छोटा होता है, जिससे एआरसी को बैंक या वित्तीय संस्था के अलग कर्ज पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्ज या तो केवल नकद या नकद और एसआर को मिलाकर लिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिग्रहण में एआरसी की अधिक भूमिका है, उन्हें सभी एसआर के मोचन तक निरंतर आधार पर प्रत्येक योजना के तहत एसआर के न्यूनतम 15 प्रतिशत का निवेश करना होगा।⁹

चरण 2: आस्ति अधिग्रहण के बाद, एआरसी समाधान के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं; योजना की अवधि प्रवर्तक द्वारा आस्ति के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने तक होती है। विभिन्न प्रकार से समाधान किया जा सकता है, जिसमें उधारकर्ता के व्यवसाय प्रबंधन में परिवर्तन और अधिग्रहण,

⁷ एफडीआई की यह बढ़ी हुई सीमा इस शर्त के अधीन थी कि किसी व्यक्तिगत विदेशी संस्थागत/पोर्टफोलियो निवेशक की शेयरधारिता एआरसी की कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

⁸ "प्रायोजकों और उधारदाताओं से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण" पर 6 दिसंबर 2019 के आरबीआई के दिशानिर्देश देखें।

⁹ अगस्त 2014 में, एआरसी के लिए न्यूनतम एसआर सदस्यता को पहले के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था।

उधारकर्ता के एक हिस्से या पूरे व्यवसाय की बिक्री या पट्टे पर देना, उधारकर्ता द्वारा देय कर्ज के भुगतान का पुनर्निर्धारण, प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन, आदि।

चरण 3: समाधान के बाद, एआरसी कर्ज की वसूली शुरू करते हैं और एसआर के मोचन पर काम करते हैं। एआरसी को बकाया कर्ज की वसूली के लिए पांच साल की अवधि की अनुमति है। हालांकि, इस अवधि को उनके बोर्डों के अनुमोदन के अधीन आठ वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

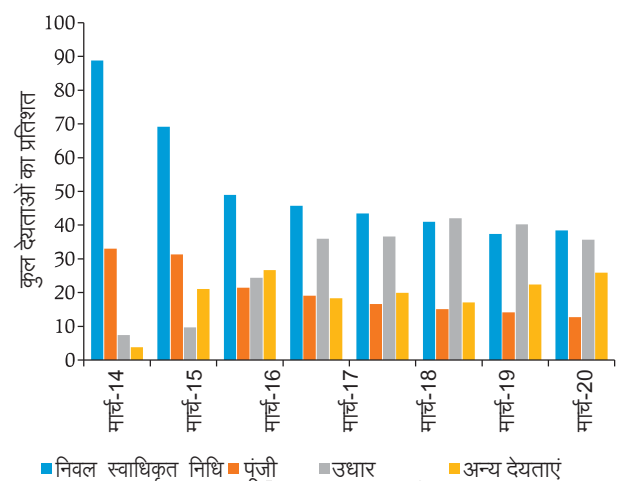
5.1 एआरसी के सामान्य परिचालन से संबंधित विशेषताएं

5.1.1 निधि के स्रोत

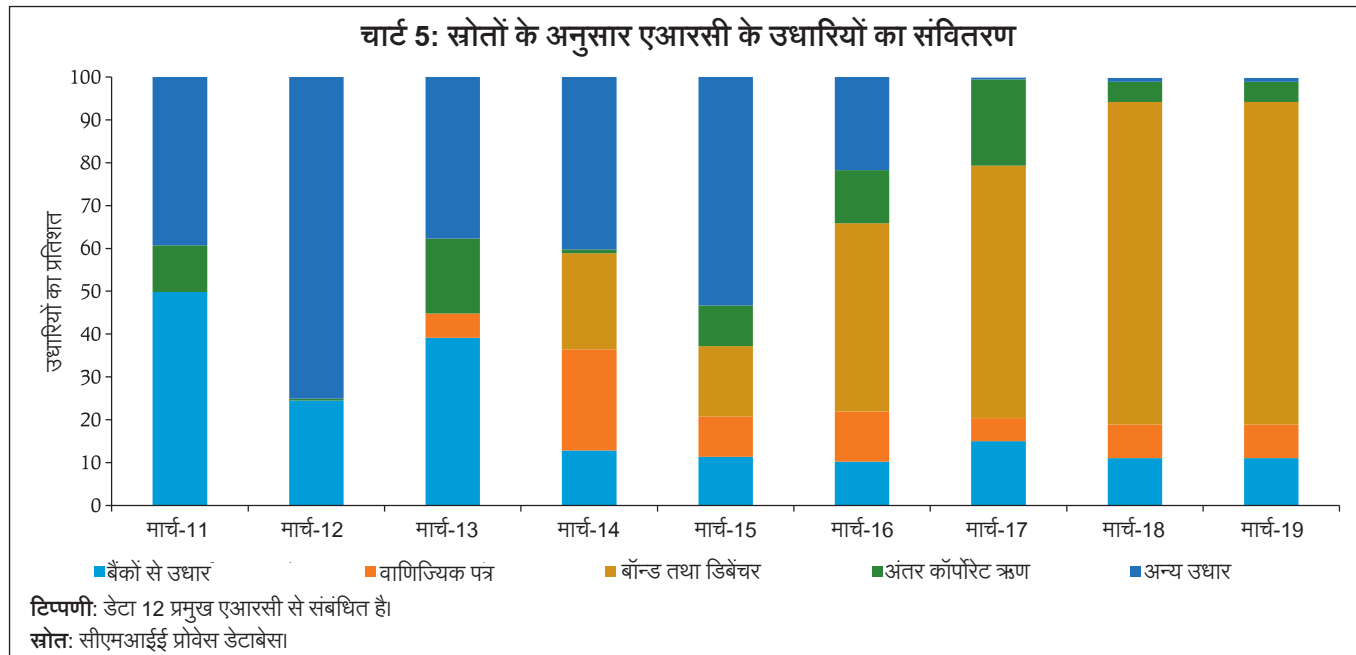
एआरसी के लिए उधार निधि का एक प्रमुख स्रोत है, जिसकी तुलना इन कंपनियों के निवल स्वाधिकृत निधि के साथ की जा सकती है (चार्ट 4)। निस्संदेह, पूंजी जुटाने में कोई बाधा सीधे इन कंपनियों की उधार पर बढ़ी हुई निर्भरता पर असर कर सकती है।

इसके अलावा, एआरसी के निधियों के स्रोत काफी हद तक बैंक केंद्रित स्वरूप के रहे हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एआरसी का पूंजी आधार मुख्यतः घरेलू स्रोतों, विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बनाया गया है, जिसमें विदेशी स्रोत मामूली हैं। एआरसी की उधारी के विवरण

चार्ट 4: प्रमुख स्रोतों के अनुसार एआरसी की देयताओं का संवितरण



टिप्पणी: पूंजी निवल स्वाधिकृत निधि का एक हिस्सा है, लेकिन वैयक्तिक शेयर को दर्शाने के लिए इसे अलग से दिखाया गया है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।



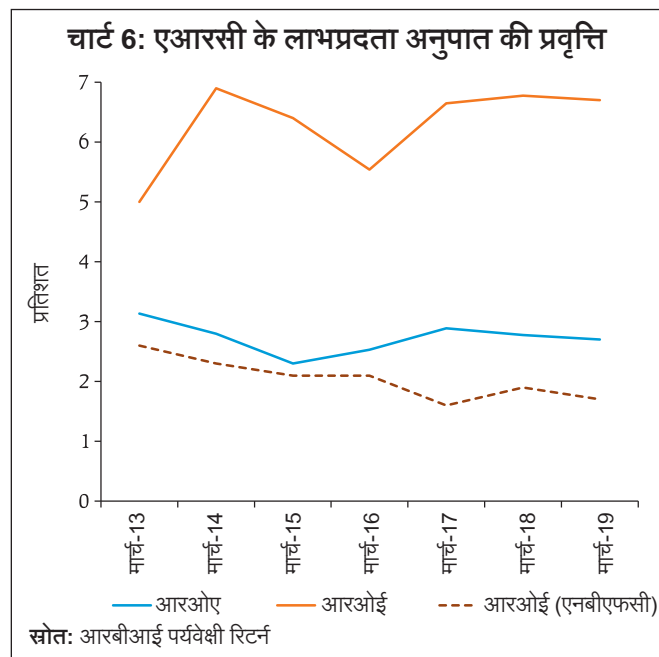
से बैंकों पर उनकी निर्भरता का पता चलता है। हाल के वर्षों में, बैंक उधारी के हिस्से में गिरावट आई है, बॉन्ड और डिबेंचर इन कंपनियों के लिए उधारी के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहे हैं (चार्ट 5)।

5.1.2 लाभप्रदता

एआरसी के लिए प्रबंधन/न्यास शुल्क, वसूली और कर्ज की अधिग्रहण लागत के बीच के अंतर से मिलने वाली राशि, और बैंकों द्वारा शीघ्र वसूली के लिए दिए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन, आय के प्रमुख स्रोत हैं। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन शुल्क एसआर के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) से जुड़ा होता है (न कि पूर्व की तरह बकाया एसआर की मात्रा पर) ताकि वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एआरसी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए, एआरसी के लिए कोई भी रिकवरी रेटिंग में कमी सीधे उनके प्रबंधन शुल्क को प्रभावित करता है।¹⁰ न्यास द्वारा किए गए खर्चों को वसूली से पहले निकाला जाता है, इसके बाद प्रबंधन शुल्क और एआरसी को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, और शेष राशि का उपयोग एसआर के मोचन के लिए किया जाता है। लीवरेज पर ब्याज लागत के अलावा एआरसी के

व्यय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के अधिग्रहण परिचालन व्यय और न्यास के मूल्यांकन के लिए किए गए शुल्क से संबंधित होता है।

एआरसी की लाभप्रदता की समग्र प्रवृत्ति से पता चलता है कि आस्तियों पर रिटर्न काफी हद तक (आरओए) 3 प्रतिशत के करीब स्थिर है (चार्ट 6)। जबकि इक्विटी पर रिटर्न में (आरओई)



¹⁰ वसूली रेटिंग के बारे में खंड 5.2.3 में चर्चा की गयी है।

2014 के बाद अत्यधिक गिरावट देखी गयी है तथा 2016 के बाद से पुनर्जीवित होकर लगभग 7 प्रतिशत के करीब है। विशेष रूप से, एआरसी का आरओए उनके एनबीएफसी समकक्षों की तुलना में अधिक है।

5.2 एआरसी के परिचालन चरण की विशिष्ट विशेषताएं

5.2.1 आस्तियों का अधिग्रहण

एआरसी आम तौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्ति अर्जित करते हैं। प्रायोजक बैंकों के साथ द्विपक्षीय सौदे करने पर प्रतिबंध है, जबकि वित्तीय संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय सौदों के लिए या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित नीलामी के लिए ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं हैं। दो प्रकारों में से, अब तक एआरसी सौदों पर नीलामी का प्रभुत्व है (चार्ट 7)।

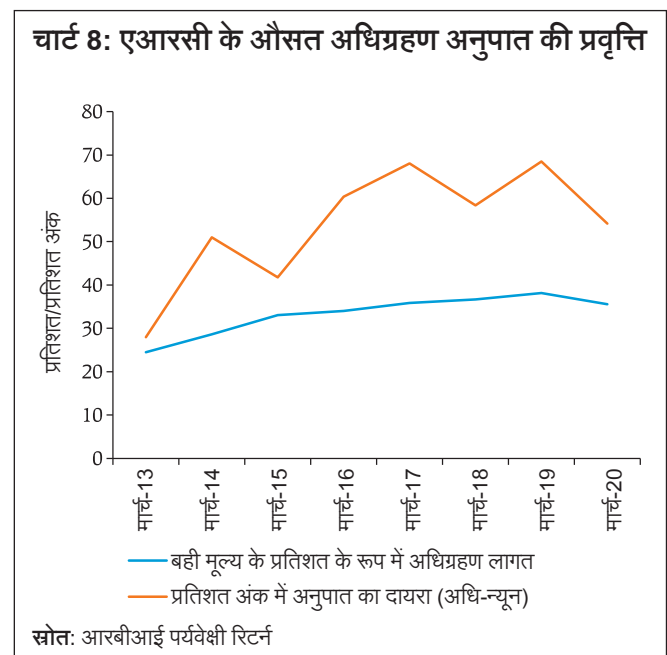
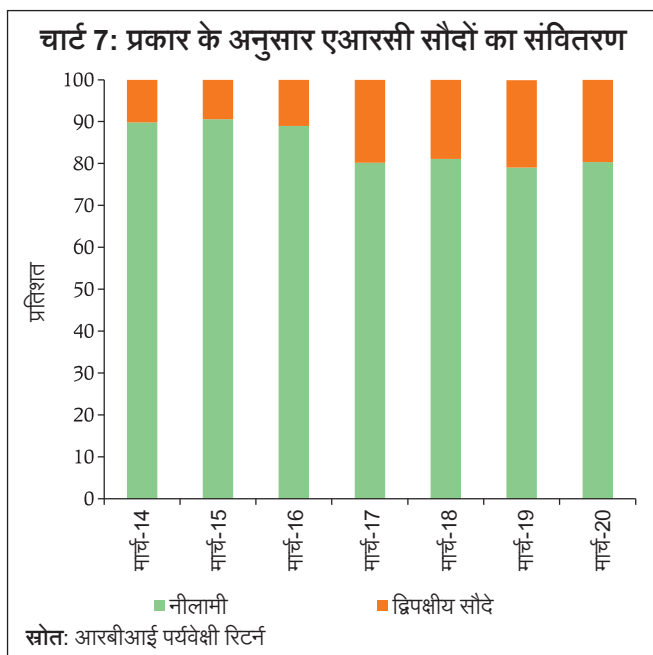
अधिग्रहण की प्रक्रिया में एआरसी के लिए अर्जित आस्तियों का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक चिंता है। यह ध्यान में रखते हुए कि एआरसी और बैंक बिक्री, सौदे के दो भाग हैं, उच्च अधिग्रहण अनुपात (आस्तियों के बही मूल्य में अधिग्रहण लागत के रूप में परिभाषित) बैंकों के पक्ष में है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कम अधिग्रहण अनुपात, और परिणामस्वरूप उच्च मार्जिन ने बैंकों को उनके बही-खातों में दबावग्रस्त आस्तियां लेने से रोक रखा है। समय के साथ, हालांकि औसत अधिग्रहण

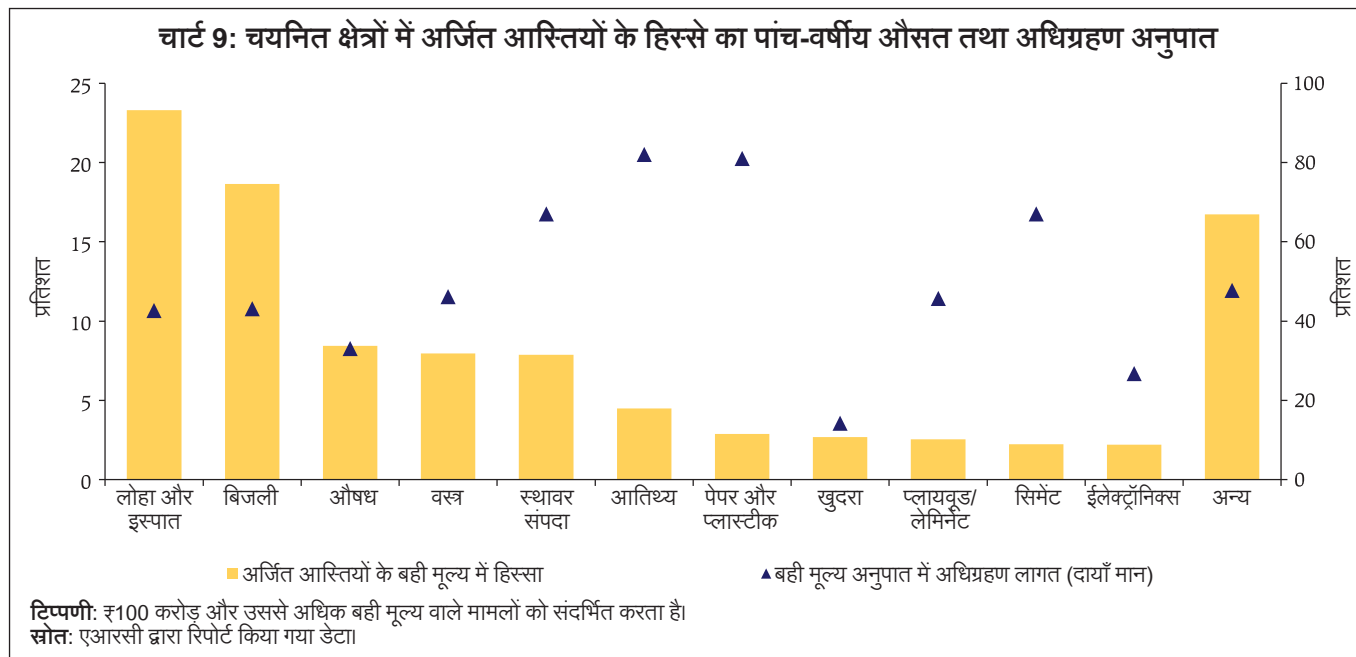
अनुपात धीरे-धीरे बढ़ा है तथा यह 30-35 प्रतिशत के दायरे में बना हुआ है। इसके अलावा, एआरसी में अधिग्रहण अनुपात में अत्यधिक अस्थिरता बनी हुई है तथा समय के साथ अस्थिरता और बढ़ती ही जा रही है (चार्ट 8)।

सभी क्षेत्रों के अधिग्रहण अनुपात में भी अत्यधिक अस्थिरता है। लोहा और इस्पात और बिजली क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अर्जित आस्तियों में अपेक्षाकृत अधिक संकेंद्रण हैं, क्योंकि वे एनपीए से भी ग्रस्त हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अधिग्रहण अनुपात काफी कम रहा है। इसके विपरीत, आतिथ्य और स्थावर संपदा का कुल अर्जित आस्तियों में एक छोटा हिस्सा है लेकिन उनका अधिग्रहण अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहा है (चार्ट 9)।

5.2.2 आस्तियों का समाधान

आस्तियों का अधिग्रहण केवल एआरसी के परिचालन की शुरुआत है; दूसरा चरण अर्जित आस्तियों के समाधान से संबंधित है। मोटे तौर पर, एक एआरसी द्वारा लिए गए समाधान दृष्टिकोण को या तो परिसमापन दृष्टिकोण या कार्यशील संस्था दृष्टिकोण या दोनों के मिलेजुले रूप में देखा जा सकता है। सटीक दृष्टिकोण का विकल्प अंतर्निहित आस्तियों की व्यवहार्यता का प्रेरक होता है।





विशेष रूप से एआरसी के समाधान प्रक्रिया को जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें ऐसे एआरसी को भी दर्शाया गया है जो अन्य तरीकों से भुगतान के स्थान पर कर्ज के पुनर्निर्धारण को पसंद करते हैं। प्रतिभूति हित को लागू करने के माध्यम से निपटायी गयी आस्तियों के प्रतिशत में समय के साथ लगातार गिरावट आई है। प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण/आस्तियों पर कब्जा करना जैसे तरीकों का, समाधान के लिए कभी कभार उपयोग किया गया है।

5.2.3 एसआर की वसूली और मोचन

एआरसी के परिचालन का तीसरा चरण एसआर की वसूली और मोचन है। एसआर की वसूली एआरसी के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एआरसी

को उनके द्वारा जारी एसआर का एनएवी प्रकट करना आवश्यक है, जिसका उपयोग निवेशकों द्वारा एसआर के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। एनएवी का निर्धारण करने के लिए, एआरसी को एक मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) से रिकवरी रेटिंग प्राप्त करनी होगी। सीआरए आम तौर पर अपनाई गई समाधान प्रक्रिया के आकलन के आधार पर अपनी रिकवरी रेटिंग निर्धारित करता है।

निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) और एयूएम का संकेंद्रण एसआर के निर्गम में भी प्रतिबिंबित होता है जिस पर पहले चर्चा की गई थी; मार्च 2020 में जारी किए गए कुल एसआर का लगभग 62 प्रतिशत केवल दो एआरसी में ही है (चार्ट 10)।

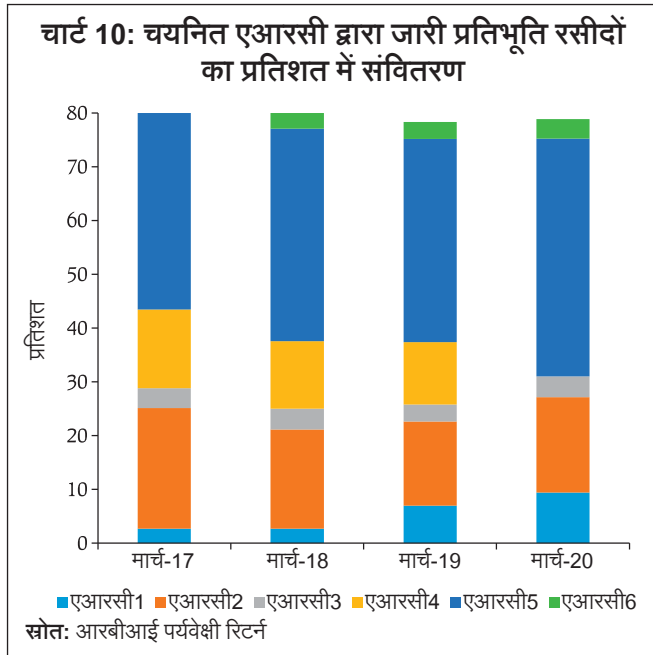
इसके अलावा, विशिष्ट सीमा से ऊपर एसआर रखने को प्रोत्साहित नहीं करने के लिए विनियमन में परिवर्तन के बावजूद बैंकों ने कुल एसआर के 70 प्रतिशत के करीब एसआर रखना जारी रखा है (चार्ट 11)।¹¹ इन लिखतों को सूचीबद्ध करने और उनकी खरीद-बिक्री को प्रोत्साहित करने को लेकर विनियामकीय दबाव होने के बावजूद, एसआर की सीमित गौण खरीद-बिक्री के

सारणी 2: समाधान की पद्धति के अनुसार कुल निपटायी गयी आस्तियों का प्रतिशत में सवितरण

समाधान की पद्धति	मार्च -16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20
1 कर्ज के भुगतान का पुनर्निर्धारण	37.0	36.5	36.8	35.7	32.0
2 प्रतिभूति हित का प्रवर्तन	32.0	35.1	31.5	28.6	26.6
3 उधारकर्ता की बकाया राशि का निपटान	30.0	24.8	25.2	28.4	26.0
4 आस्तित्व पर कब्जा	2.0	3.9	6.2	7.2	1.5
5 व्यवसाय की बिक्री	0.0	0.4	0.3	0.1	13.9

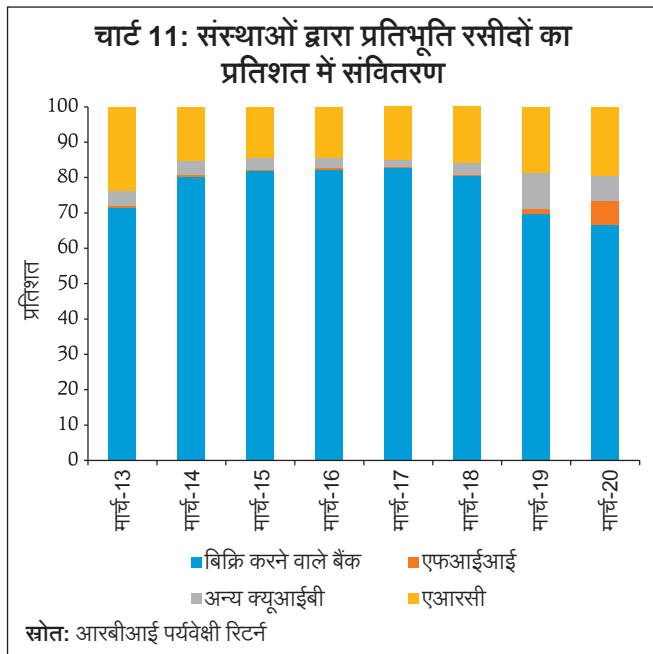
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।

¹¹ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा आस्तित्व की बिक्री वास्तविक बिक्री में परिणत होती है, एसआर रखने वाले बैंकों के लिए उनकी बेची गई आस्तियों द्वारा समर्थित एक सीमा निर्दिष्ट की गई थी। 1 अप्रैल 2018 से इस सीमा को उत्तरोत्तर 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। सीमा से अधिक एसआर धारिता उच्च प्रावधान आवश्यकता के अधीन है।



लिए बिक्री करने वाले बैंकों का एसआर धारिता में प्रभुत्व का वर्णन प्रायः एक कारण के रूप में किया जाता है।¹²

बकाया एसआर का अवधि-वार ब्यौरा एआरसी की बही में पुराने एसआर का सकेंद्रण दर्शाता है। यह देखते हुए कि एआरसी



¹² सार्वजनिक पेशकश और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों की सूची पर 26 जून 2018 की सेबी की अधिसूचना देखें।

सारणी 3: प्रतिभूति रसीदों का अवधि-वार ब्यौरा (मार्च 2020 की स्थिति)

वर्ष	कुल बकाया प्रतिभूति रसीदें (₹ करोड़)	अवधि (वर्ष)	राइट ऑफ का नियत वर्ष
2912-13 तथा उससे पूर्व	3,910 (3.6)	8 वर्ष से अधिक	2020-21
2013-14	16,393 (15.3)	7	2021-22
2014-15	15,333 (14.2)	6	2022-23
2015-16	9,401 (8.7)	5	2023-24
2016-17	15,603 (14.5)	4	2024-25
2017-18	14,834 (13.8)	3	2025-26
2018-19	18,084 (16.8)	2	2026-27
2019-20	14,318 (13.3)	1	2027-28
कुल	1,07,877 (100.0)	-	-
भारत औसत अवधि	-	4.1	-

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2020 को बकाया प्रतिभूति रसीदों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।

के पास एसआर को भुनाने के लिए पांच वर्ष की अवधि (आठ साल तक बढ़ायी जा सकती है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी), उनके मोचन प्रदर्शन को जारी किए गए एसआर की अवधि से प्रेरित होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, एसआर के बकाया स्टॉक में नए एसआर की प्रधानता होगी। हालांकि, मार्च 2020 तक बकाया एसआर में से लगभग 42 प्रतिशत पांच साल से अधिक अवधि के थे और राइट-ऑफ से बचने के लिए अगले चार वर्षों में उनका मोचन करना आवश्यक है (सारणी 3)।

6. निष्कर्षणात्मक टिप्पणियां

एआरसी भारत में आस्ति समाधान के लिए संस्थागत इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग रहा है। कई अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने बैंकिंग संकट या संकट जैसी स्थितियों के बाद पूर्व-निर्धारित अवधि के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनियों के सार्वजनिक क्षेत्र मॉडल का प्रयोग किया, भारत ने अपने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के भाग के रूप में एआरसी को निजी क्षेत्र की संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया। संविधान और अधिदेश में अंतर को देखते हुए, भारतीय एआरसी के विकास की प्रक्रिया

अन्य देशों में उनके समकक्षों की तुलना

भारत में एआरसी के विकास को उनकी संख्या और प्रबंधनाधीन आस्तियां दोनों के संदर्भ में वृद्धि और सुस्ती के चरणों द्वारा अंकित किया गया है। समष्टि आर्थिक स्थितियों और विनियामक वातावरण ने उन्हें आकार दिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक रूप से एआरसी उद्योग को मजबूत करने, बैंकों द्वारा एनपीए की वास्तविक बिक्री सुनिश्चित करने, समाधान की प्रक्रिया में एआरसी की भागीदारी बढ़ाने और एसआर के लिए बाजार को गहरा करने के लिए विनियामक परिवर्तन किए गए हैं।

भारतीय एआरसी उद्योग की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं: सबसे पहले, समय के साथ एआरसी की संख्या में वृद्धि के बावजूद, एयूएम और संबंधित एसआर जारी किए गए, और निवल स्वाधिकृत निधि के मामले में उद्योग में संकेंद्रण रहा है। दूसरा विनियामक प्रोत्साहन के बावजूद, और इस प्रकार इन कंपनियों के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए, वे मुख्य रूप से पूंजी के घरेलू स्रोतों, विशेष रूप से बैंकों पर निर्भर रहे हैं। तीसरे, इन कंपनियों के निजी स्वरूप को देखते हुए, वे अपने निधि के एक प्रमुख स्रोत के रूप में, विशेष रूप से बैंकों से उधार पर निर्भर हैं। यह देखते हुए कि बैंक न केवल एआरसी के प्रमुख शेयरधारक और उधारदाता हैं, बल्कि एआरसी को एनपीए के विक्रेता भी हैं, यह निगरानी करना आवश्यक हो सकता है कि क्या बैंकों और इन संस्थाओं के बीच निधि का कोई अप्रत्यक्ष संचलन हो रहा है। इस तरह के संचलन से एनपीए की वास्तविक बिक्री और एआरसी उद्योग के समग्र विकास पर असर पड़ सकता है।

एआरसी के व्यवसाय परिचालन को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे, आस्ति का अधिग्रहण, आस्ति का समाधान, और अंत में, एसआर की वसूली और मोचना। इनमें से प्रत्येक चरण की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। सबसे पहले, एआरसी उद्योग के लिए वर्तमान अधिग्रहण अनुपात लगभग 35 प्रतिशत है, जो एआरसी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में अत्यधिक अस्थिरता है। दूसरे, एआरसी ने मुख्य रूप से समाधान की एक पद्धति के रूप में भुगतान दायित्वों के पुनर्निर्धारण का

सहारा लिया है; प्रतिभूति हितों को लागू करने के माध्यम से समाधान में समय के साथ गिरावट देखी गई है। तीसरा, एआरसी की बहियों में पुराने एसआर का काफी संकेंद्रण है।

आईबीसी, 2016 भारत में आस्ति समाधान इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक मील का पत्थर रहा है। हाल के वर्षों में आईबीसी के माध्यम से वसूल की गई आस्तियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जबकि एआरसी के माध्यम से वसूल की गई आस्तियों के प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। हालांकि, विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल की गई कुल आस्ति का लगभग 30 प्रतिशत एआरसी के माध्यम से है और आईबीसी के बाद भी एआरसी आस्ति समाधान के लिए एक पूरक तंत्र बनी हुई है।

कोविड-19 महामारी के बाद बैंकों और एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में परिवर्तन से एआरसी पर अधिक ध्यान आकर्षित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए का समाधान करने के लिए एक नई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की शुरुआत भी मौजूदा एआरसी परिचालन को आकार दे सकती है। भारतीय एआरसी उद्योग में एक अच्छी तरह से पूंजीकृत और अच्छी तरह से संरेखित संस्था के प्रवेश के लिए एक निश्चित गुंजाइश है; ऐसी संस्था आस्ति समाधान तंत्र को और मजबूत करेगी।

संदर्भ:

Bergström, C., P. Englund, and P. Thorell (2003), "Securum and the Way Out of the Banking Crisis", *Summary of a Report commissioned by SNS (Centre for Business and Policy Studies)*, Stockholm.

Bhagwati, J., M. Shuheeb Khan and R. R. Bogathi (2017), "Can Asset Reconstruction Companies (ARCs) be Part Solution to the Indian Debt Problem?", *ICRIER Working Paper 338*.

Cerruti, C. (2018), "Public Asset Management Companies", World Bank presentation at <https://pubdocs.worldbank.org/en/531571527523031777/NPL-Conference-Day1-8-Caroline-Cerruti.pdf>

- Cerruti, C. and R. Neyens, (2016), Public Asset Management Companies- A Toolkit, *World Bank Group*.
- Dreyer, M., (2020), *Preliminary YPFS discussion Draft, Danaharta*.
- Ernst and Young (2020), "Management of Non-performing Loans", Presentation at www.assets.ey.com.
- Fung, B., J. George, S. Hohl and G. Ma (2004), "Public Asset Management Companies in East Asia: A Comparative Study", FSI Occasional Paper No. 3.
- IBBI (2019), *Understanding the IBC- A Handbook*, New Delhi.
- Reserve Bank of India (2018), *Report of the Expert Committee on NPAs and Frauds*, Mumbai.
- World Bank (1997), *Implementation Completion Report - Republic of Ghana*.